



IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

60 Days Week-5&6 Compilation



DELHI

BANGALORE

5B, Pusa Road, Karol
Bagh, New Delhi - 110005.
Landmark: Just 50m from
Karol Bagh Metro Station,
GATE No. 8 (Next to
Croma Store)
Ph: 0114167500

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar
Service Road, Vijaynagar, Bangalore
560040. PH: 09035077800 /
7353277800



support@iasbaba.com



www.iasbaba.com

Q.1) संसद के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के आधार पर किया जाता है।
2. वर्तमान लोकसभा अपनी अधिकतम सदस्य संख्या (सदस्यों के संदर्भ में) पर कार्य कर रही है।
3. संसद में नामित सदस्य रहने का प्रावधान एक स्थायी विशेषता है जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) उपरोक्त सभी
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.1) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य
राज्य सभा में सीटों का आवंटन संविधान के पारित होने के समय उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों से ज्ञात प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में रखा गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के भाग IVA में केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित राज्यसभा की सीटों को भरने का तरीका बताया गया है।	लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में, लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य से राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।	राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्य सभा में नामित करता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। यदि समुदाय पर्याप्त रूप से लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो राष्ट्रपति एंग्लो-इंडियन समुदाय से दो सदस्यों को नामित कर सकता है। मूल रूप से, यह प्रावधान 1960 तक संचालित था, लेकिन 2020 तक इसे 95 वें संशोधन अधिनियम, 2009 से बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, यह लोकसभा के लिए एक स्थायी विशेषता नहीं है।

Q.2) संविधान प्रतिनिधित्व की एकरूपता (uniformity of representation) सुनिश्चित करता है

1. विभिन्न राज्यों के बीच
2. विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के बीच।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
-------	-------

सत्य	असत्य
संविधान यह सुनिश्चित करता है कि दो तरह से प्रतिनिधित्व की एकरूपता हो: (a) विभिन्न राज्यों के बीच, और (b) एक ही राज्य में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के बीच।	
1. प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटें इस तरह से आवंटित की जाती हैं कि सीटों की संख्या और उसकी आबादी के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान हो। यह प्रावधान छह लाख से कम आबादी वाले राज्य पर लागू नहीं होता है। 2. प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके लिए आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात पूरे राज्य में समान हो।	

Q.3) भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- राष्ट्रपति हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय लेने वाले प्राधिकारी हैं।
- राष्ट्रपति को, मंत्रियों की परिषद पर विचार करने के लिए, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिसे परिषद द्वारा नहीं माना गया है, प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।
- राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं।
- पुडुचेरी और दिल्ली के मामले में, राष्ट्रपति नियम बनाकर कानून बना सकता है, लेकिन केवल तभी जब विधानसभा निलंबित या भंग हो।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1, 3 और 4
- 2 और 3
- 1, 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.3) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	सत्य	असत्य
मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।	अनुच्छेद 78 के अनुसार, राष्ट्रपति को, मंत्रियों की परिषद पर विचार करने के लिए, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिसे परिषद द्वारा नहीं माना गया है, प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।	राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं।	केवल पुडुचेरी (दिल्ली नहीं) के मामले में, राष्ट्रपति विनियम बनाकर विधान लागू कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब विधानसभा निलंबित या भंग कर दी गयी हो।

Q.4) एक सदस्य पर दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता का आरोप लगता है

- यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए निर्वाचित होता है
- यदि वह सदन में वोट देते समय अनुपस्थित होता है या अपनी राजनीतिक पार्टी द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत करता है;

3. यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
4. यदि कोई भी नामित सदस्य 6 महीने से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1, 2 और 3
- b) 1 और 2
- c) 2, 3 और 4
- d) उपरोक्त सभी

Q.4) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	असत्य

एक सदस्य दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है:

1. यदि वह स्वैच्छिक रूप से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए निर्वाचित होता है;
2. यदि वह सदन में वोट देते समय अनुपस्थित रहता है या अपनी राजनीतिक पार्टी द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत मतदान करता है;
3. यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है;
4. यदि कोई भी नामित सदस्य छह महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

Q.5) लोकसभा के अध्यक्ष (speaker) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. अध्यक्ष के पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
2. वह भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतिम व्याख्याकार हैं।
3. कोरम के अभाव में, वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही सदन को निलंबित कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.5) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य

लोकसभा अध्यक्ष संसद के सदस्यों में से एक है। वह प्रो-टेम स्पीकर द्वारा अन्य सदस्यों के साथ शपथ लेता है। पुष्टि की कोई अलग शपथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाती है। तकनीकी रूप से कहे तो लोकसभा अध्यक्ष, देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की तरह अकेले कोई शपथ नहीं लेते हैं।

वह निम्न प्रावधानों के अंतिम व्याख्याकार हैं
(a) भारत का संविधान,
(b) लोक सभा के व्यवसाय की प्रक्रिया और आचरण के नियम, और
(c) सदन के भीतर संसदीय पूर्ववर्ती उदाहरण (precedents)।

वह सदन को स्थगित कर सकता है या कोरम के अभाव में बैठक निलंबित कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

Q.6) राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें

1. अध्यक्ष पहली बार में मतदान कर सकता है जब उसके निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन है, जबकि सभापति मतदान नहीं कर सकता है।
2. अध्यक्ष की तरह, सभापति भी सदन का सदस्य नहीं होता है।
3. अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.6) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
सभापति सदन में उपस्थित हो सकते हैं और बोल सकते हैं तथा बिना मतदान के इसकी कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकते हैं, यहां तक ऐसे समय में (जबकि अध्यक्ष पहली बार में ही मतदान कर सकते हैं, जब उनके हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के विचाराधीन हो)।	अध्यक्ष (जो सदन का सदस्य है) के विपरीत, सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है।	अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

Prelims 2020 Exclusive :Current Affairs Classes

Beat the Heat of Current Affairs Prelims 2020 in 12 Uber Cool Sessions by Tauseef Ahmad (One of the Founders of IASbaba)

MOST PROBABLE PRELIMS
CURRENT AFFAIRS TOPICS
FROM PAST 1.5 YEARS WILL
BE COVERED IN 12 SESSIONS



CRISP AND ORGANISED
NOTES/CONTENT TO MAKE
YOUR REVISION EASIER



Starts 15th April

Q.7) जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान निहित हैं?

1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
2. निर्वाचक नामावली तैयार करना
3. संसद के सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता
4. मतदाताओं की योग्यता

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1,2 और 3
- b) 1,2 और 4
- c) 2,3 और 4

d) 1,2,3 और 4

Q.7) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	सत्य

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

1. लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों का आवंटन।
2. लोक सभा और विधान सभा के चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
3. ऐसे चुनाव में मतदाता की योग्यता
4. निर्वाचक नामावली की तैयारी।

संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों को चुनाव के वास्तविक आचरण के प्रावधान, इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराध, तथा चुनाव का विवाद निर्णय बाद के अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रदान किए गए हैं।

Q.8) लोकसभा के विघटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यदि सदन अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो राष्ट्रपति के आदेश पर विघटन को रद्द किया जा सकता है।
2. लोकसभा में सभी लंबित विधेयक विघटन के मामले में समाप्त हो जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.8) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो विघटन अपरिवर्तनीय होता है।	लोकसभा में लंबित सभी विधेयक इसके विघटन पर (चाहे लोकसभा में उत्पन्न हो या राज्यसभा द्वारा इसे प्रेषित किया गया हो) समाप्त हो जाते हैं।

Q.9) प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सदस्य मंत्रियों के साथ-साथ निजी सदस्यों से भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
2. एक अल्प सूचना प्रश्न (short notice question) का मौखिक उत्तर या लिखित उत्तर हो सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
मंत्रियों के अलावा, निजी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।	एक अल्प सूचना प्रश्न वह है जो दस दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।

Q.10) विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है।
2. यह एक सदस्य द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है जब उसे लगता है कि एक मंत्री ने किसी मामले में तथ्यों को छिपाया है।
3. इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की निंदा (censure) के लिए किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.10) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
विशेषाधिकार प्रस्ताव एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है।	किसी सदस्य द्वारा इसे स्थानांतरित किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्यों को देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।	इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है।

Q.11) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. प्रत्येक सत्र का पहला दिन राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है।
2. सरकार को गिरने से बचाने के लिए 'धन्यवाद प्रस्ताव' को केवल लोकसभा में पारित करने की आवश्यकता होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
प्रत्येक आम चुनाव के बाद का पहला सत्र तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है।	राष्ट्रपति के इस संबोधन पर संसद के दोनों सदनों में 'धन्यवाद प्रस्ताव' नामक प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा के अंत में, मतदान के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। यह प्रस्ताव प्रत्येक सदन में पारित होना चाहिए। अन्यथा, यह सरकार की हार मानी जाती है।

Q.12) राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं?

- अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधनों से संबंधित विधेयक।
- विधेयक जिसमें भारत के समेकित निधि से व्यय शामिल हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 में उल्लिखित के अलावा अन्य प्रावधान हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, न कि धन विधेयकों या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर। कथन 1 संवैधानिक संशोधन विधेयक है कथन 2 वित्त विधेयक है	

Q.13) बजट अधिनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करें

- राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी।
- संसद एक कर को कम या बढ़ा सकती है लेकिन इसे समाप्त नहीं कर सकती।
- भारत के समेकित कोष पर भारित व्यय पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.13) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य

राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी।	संसद एक कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है।	भारत के समेकित कोष पर भारित व्यय संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इस पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।
--	--	--

Q.14) निम्नलिखित में से कौन से कटौती प्रस्तावों को सही ढंग से परिभाषित किया गया है?

1. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव- यह बताता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये किया जाएगा।
2. आर्थिक कटौती प्रस्ताव- इसमें कहा गया है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाएगी।
3. नीतिगत कटौती प्रस्ताव- इसमें कहा गया है कि मांग की राशि एक निर्दिष्ट राशि से कम की जाए।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) 2 और 3
- c) उपरोक्त सभी
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.14) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य
सांकेतिक कटौती प्रस्ताव एक विशिष्ट शिकायत को रेखांकित करता है जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की गई है।	आर्थिक कटौती प्रस्ताव उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रस्तावित व्यय में प्रभावित हो सकती है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि (जो या तो संपूर्ण मांग में कमी या मांग की वस्तु में कमी) कम हो सकती है।	नीतिगत कटौती प्रस्ताव मांग को अंतर्निहित नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रूपए कर दिया जाएगा। सदस्य एक वैकल्पिक नीति को भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

Q.15) निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान तब दिया जाता है, जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्विनियोजन (reappropriation) द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है?

- a) अनुपूरक अनुदान
- b) सांकेतिक अनुदान
- c) अतिरिक्त अनुदान
- d) आधिक्य अनुदान

Q.15) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	असत्य	असत्य
अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) तब दिया जाता है जब संसद द्वारा वर्तमान वित्तीय	सांकेतिक अनुदान (Token Grant) तब प्रदान किया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय	अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant) तब दिया जाता है जब उस वर्ष के बजट में विचार नहीं	आधिक्य अनुदान (Excess Grant) उस समय प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए

वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम के माध्यम से अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है।	को पूरा करने के लिए धनराशि फिर से उपलब्ध कराई जा सकती है। एक सांकेतिक राशि (1 रूपए की) के अनुदान की मांग लोकसभा में मत के लिए प्रस्तुत की जाती है और यदि अनुमोदन दिया जाता है, तो धन उपलब्ध कराया जाता है। पुनर्विनियोजन में एक से दूसरे तक धन का हस्तांतरण शामिल है। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं है।	किए गए कुछ नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान एक आवश्यकता उत्पन्न हुई हो।	दी गई राशि से अधिक राशि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर खर्च की गई हो। यह वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है। मतदान के लिए लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
---	--	---	---

Q.16) भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकते हैं।
2. भारत की आकस्मिक निधि को संसद के निपटान (disposal) के अंतर्गत रखा गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
संविधान ने 'भारत की आकस्मिकता निधि' की स्थापना के लिए संसद को अधिकृत किया, जिसमें कानून द्वारा निर्धारित राशियों का समय-समय पर भुगतान किया जाता है। तदनुसार, संसद ने 1950 में भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम को अधिनियमित किया।	इस कोष को राष्ट्रपति के निपटान के अंतर्गत रखा गया है, तथा वह संसद से इसके प्राधिकरण के लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसमें से अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। यह धन राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के पास होता है।

Q.17) संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया है, जो निम्नलिखित परिस्थितियों में है

1. अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी करना।
2. दो राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना।
3. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के मामले में।
4. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1,2 और 3
- b) 1,2 और 4
- c) 1,3 और 4

d) उपरोक्त सभी

Q.17) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	असत्य	सत्य	सत्य

संविधान निम्नलिखित पाँच असामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों (जो वर्तमान में 61 विषय, मूल रूप से 66 विषय हैं) पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देता है:

(a) जब राज्यसभा उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।
 (b) जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो।
 (c) जब दो या अधिक राज्य संसद से इसके लिए एक संयुक्त अनुरोध करते हैं।
 (d) जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों और सम्मेलनों को प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो।
 (e) जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है।

Q.18) संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें

1. गिरफ्तार न किए जाने का विशेषाधिकार केवल दीवानी और निवारक निरोध मामलों के लिए उपलब्ध है तथा आपराधिक मामलों के लिए नहीं।
2. न्यायालयों को संसदीय समितियों की कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए निषिद्ध किया गया है।
3. सदस्य साक्ष्य देने से तथा एक न्यायालय में लंबित मामले में एक गवाह के रूप में प्रस्तुत होने से इंकार कर सकते हैं, जब संसद सत्र चल रहा होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.18) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य

सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान और शुरुआत से 40 दिन पहले और एक सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में उपलब्ध है, न कि आपराधिक मामलों या निवारक निरोध के मामलों में।

न्यायालयों को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए निषिद्ध किया जा सकता है।

सदस्यों को जूरी सेवा से छूट दी गई है। सदस्य साक्ष्य देने से तथा एक न्यायालय में लंबित मामले में एक गवाह के रूप में प्रस्तुत होने से इंकार कर सकते हैं, जब संसद सत्र चल रहा होता है।

Q.19) लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
2. एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।
3. समिति के निर्णय मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.19) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत पहली बार की गई थी और तब से यह अस्तित्व में है।	एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।	इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं तथा मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। यह एक कार्यकारी निकाय नहीं है तथा इसलिए, एक आदेश जारी नहीं कर सकता है। केवल संसद ही इसके निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय ले सकती है।

Q.20) अध्यादेशों (ordinances) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो।
- अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए परिस्थितियों के अस्तित्व पर राष्ट्रपति की संतुष्टि दुर्भावना (malafide) के आधार पर न्यायोचित है।
- संविधान में उल्लिखित किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो क्योंकि एक कानून दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है और अकेले एक सदन द्वारा नहीं।	राष्ट्रपति केवल उसी समय अध्यादेश ला सकते हैं जब वह संतुष्ट हों कि परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। 1978 के 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद, राष्ट्रपति की संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण के आधार पर न्यायोचित है।	एक अध्यादेश केवल उन विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है (इस प्रकार यह राज्य सूची से विषयों को बाहर करती है)।

Q.21) भारत में राज्यपाल के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।
2. संविधान के अनुसार, राज्यपाल को, उस राज्य के लिए, एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, जहां उसे नियुक्त किया गया है।
3. राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय राज्यपाल को हटाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.21) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
जैसा कि 1979 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय दिया गया था कि, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।	विकसित किए गए कन्वेंशनों के अनुसार, राज्यपाल को उस राज्य के लिए, बाहरी व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है।	राज्यपाल के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती है और न ही कोई निश्चित कार्यकाल होता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

Q.22) राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है और हटाता है।
2. वह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है।
3. वह चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.22) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।	वह राज्य में विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। वह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है।	वह चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है।

Q.23) निम्नलिखित में से किस मामले में, राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य है?

1. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विरोध करने वाला विधेयक।
2. राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालने वाला विधेयक।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.23) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकता है, यदि वह निम्न प्रकृति का हो: (लेकिन यह अनिवार्य नहीं है) (i) अल्ट्रा-वायर्स, जो कि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। (ii) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विरोधी हो। (iii) देश के बड़े हित का विरोधी हो। (iv) गंभीर राष्ट्रीय महत्व का हो। (v) संविधान के अनुच्छेद 31 ए के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।	जब राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद एक विधेयक राज्यपाल को प्रेषित किया जाता है, तो वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है। एक मामले में ऐसा आरक्षण अनिवार्य है, अर्थात्, जहां राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो।

ONE STOP DESTINATION FOR ALL YOUR CURRENT AFFAIRS NEEDS



BABAPEDIA

UPDATED ON A DAILY BASIS

PRECISE AND CRISP CURRENT AFFAIRS NOTES

NO NEED TO MAKE NOTES FOR CURRENT AFFAIRS

ONE OF ITS KIND COMPENDIUM OF CURRENT AFFAIRS

SUBSCRIBE NOW

The most organized Platform for Current Affairs Preparation.

Highest Hit Ratio in Prelims (Current Affairs)

Highly Recommended by UPSC Toppers - Rank 4, 6, 9, 14, etc.

Q.24) निम्नलिखित में से किस मामले में, राज्यपाल को, हालांकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद से परामर्श करना पड़ता है, आखिरकार वह अपने विवेक से कार्य करता है?

1. मणिपुर राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन।
2. राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक का आरक्षण।
3. हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना।
4. मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जब कार्यालय में मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तथा कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 3
- 1,2 और 3
- 2 और 4
- उपरोक्त सभी

Q.24) Solution (a)

कथन 1	कथन 3	कथन 2	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य
कुछ विशेष उत्तरदायित्वों के मामले में, राज्यपाल को, हालांकि मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद से परामर्श करना पड़ता है, लेकिन अंत में, वह अपने विवेक से कार्य करता है। वे इस प्रकार हैं: 1. महाराष्ट्र- विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना। 2. गुजरात-सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना। 3. नागालैंड- राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में उस समय तक, जब तक नागा पहाड़ी-तुएन-सांग क्षेत्र में आंतरिक अशांति जारी है। 4. असम- जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। 5. मणिपुर - राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 6. सिक्किम- शांति के लिए और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए। 7. अरुणाचल प्रदेश- राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में। 8. कर्नाटक - हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना	राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक के आरक्षण के मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार है।	मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल के पास स्थितिजन्य विवेकाधिकार होता है, जब राज्य विधान सभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब कार्यालय में मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है।	

Q.25) राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.25) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
-------	-------

सत्य	सत्य
किसी राज्य में मंत्रियों की परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। लेकिन, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान 2003 के 91 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।	राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटा सकता है।

Q.26) राज्य विधान परिषद के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. राज्यपाल किसी राज्य में विधान परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है।
2. राज्य विधानसभा एक विधान परिषद की संरचना को संशोधित करने के लिए अधिकृत है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान विधान परिषद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.26) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य
प्रमुख (Chairman) का चुनाव परिषद अपने सदस्यों में से ही करती है।	परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई और न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निश्चित की गई है। हालांकि संविधान ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय की है, संसद द्वारा परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या तय की जाती है।	विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात् यह एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है।

Q.27) विधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सभी राज्यों के लिए इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निश्चित की गई है।
2. कुछ राज्यों की विधानसभाओं में कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.27) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
-------	-------

असत्य	सत्य
इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निश्चित की गई है। हालाँकि, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में, न्यूनतम संख्या 30 तथा मिज़ोरम और नागालैंड के मामले में, क्रमशः 40 और 46 है।	सिक्किम और नागालैंड में विधानसभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

Q.28) निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्य विधायिका की सीट रिक्त घोषित की जाती है

1. इसकी अनुमति के बिना तीस दिनों की अवधि के लिए सभी बैठक से सदस्य की अनुपस्थिति होने पर।
2. यदि सीट के लिए चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किए जाने हेतु विचाराधीन है।
3. यदि सदस्य संविधान में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 3
- b) 1 और 2
- c) केवल 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.28) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
राज्य विधायिका का एक सदन किसी सदस्य की सीट के रिक्तीकरण की घोषणा तब कर सकता है जब वह उसकी अनुमति के बिना अपनी सभी बैठक से साठ दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहा हो।	किसी सदस्य को राज्य विधान सभा के किसी भी सदन में अपनी सीट खाली करनी पड़ती है, यदि उसका चुनाव न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तथा यह तब तक नहीं किया जाता है, जब तक कि वह न्यायालय में विचाराधीन हो।	यदि राज्य विधायिका का सदस्य किसी भी अयोग्यताओं के अधीन हो जाता है, तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है।

Q.29) निम्नलिखित में से कौन एक राज्य विधानसभा में अध्यक्ष की शक्ति / कर्तव्य नहीं है?

- a) वह विधानसभा के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है।
- b) वह सदन का नेता होता है।
- c) वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है।
- d) वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तथा इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।

Q.29) Solution (b)

कथन a	कथन c	कथन d	कथन b
सत्य	सत्य	सत्य	असत्य

अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य हैं:

1. वह अपने कार्य संचालन और उसकी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए विधानसभा में आदेश और व्यवस्था को बनाए रखता है। यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उनकी अंतिम शक्ति है।
2. वह निम्न प्रावधानों के सदन के भीतर अंतिम व्याख्याकार हैं (a) भारत के संविधान, (b) विधानसभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया और आचरण के नियम, और (c) विधायी पूर्ववर्ती उदाहरण (legislative precedents)।
3. वह विधानसभा को स्थगित कर देता है या कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर देता है।
4. वह पहली बार में वोट नहीं करता है। लेकिन, वह एक बराबरी के मामले में एक निर्णायक वोट डाल सकते हैं।
5. वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की 'गुप्त' बैठक की अनुमति दे सकता है।
6. वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तथा इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।
7. वह दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दलबदल के आधार पर, विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है।
8. वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष होते हैं।

मुख्यमंत्री सदन के नेता होता है।

Q.30) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य विधायिका के सदन का तब से ही सत्रावसान किया जा सकता है, जब उसका अनिश्चित कालीन स्थगन (adjourned sine die) घोषित कर दिया जाता है।
2. स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है, जबकि अनिश्चित कालीन स्थगन के लिए, यह राष्ट्रपति और सदन के पीठासीन अधिकारी, दोनों के पास होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.30) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) सत्र का कारोबार पूरा होने पर सदन को स्थगित करने की घोषणा करता है। अगले कुछ दिनों के भीतर, राज्यपाल सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है। हालाँकि, राज्यपाल सत्र में चलने वाले सदन का भी सत्रावसान कर सकता है।	एक स्थगन एक निर्दिष्ट समय के लिए बैठकों को निलंबित करता है जो घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। अनिश्चित कालीन स्थगन का मतलब है कि अनिश्चित काल के लिए राज्य की विधायिका की बैठक को समाप्त करना। स्थगन के साथ-साथ अनिश्चित कालीन स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।

Q.31) भाग XXI के तहत विशेष प्रावधान, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रदान नहीं किए गए हैं?

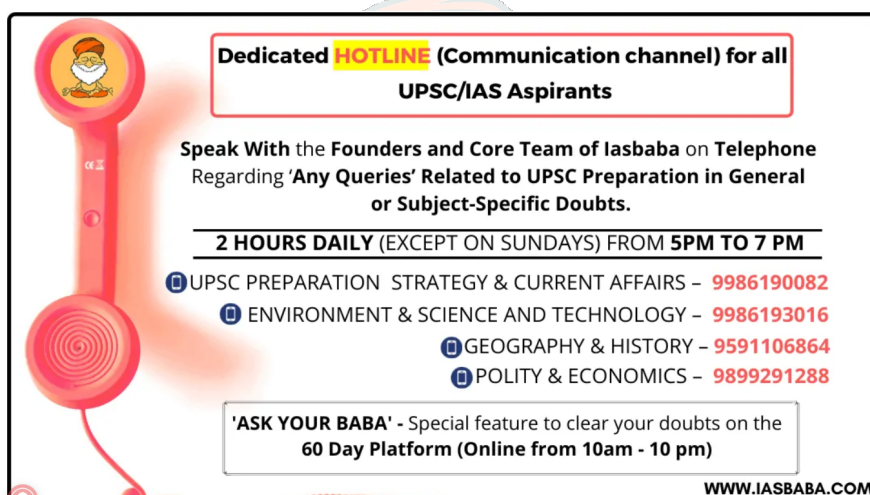
- a) नागालैंड

- b) गोवा
c) सिक्किम
d) पंजाब

Q.31) Solution (d)

कथन a	कथन b	कथन c	कथन d
सत्य	सत्य	सत्य	असत्य

संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-J में बारह राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान हैं।



Dedicated **HOTLINE (Communication channel) for all UPSC/IAS Aspirants**

Speak With the Founders and Core Team of Iasbaba on Telephone Regarding 'Any Queries' Related to UPSC Preparation in General or Subject-Specific Doubts.

2 HOURS DAILY (EXCEPT ON SUNDAYS) FROM 5PM TO 7 PM

- UPSC PREPARATION STRATEGY & CURRENT AFFAIRS – **9986190082**
- ENVIRONMENT & SCIENCE AND TECHNOLOGY – **9986193016**
- GEOGRAPHY & HISTORY – **9591106864**
- POLITY & ECONOMICS – **9899291288**

'ASK YOUR BABA' - Special feature to clear your doubts on the 60 Day Platform (Online from 10am - 10 pm)

WWW.IASBABA.COM

Q.32) राज्य विधानमंडल में भाषा के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- संविधान ने घोषणा की है कि राज्य विधानमंडल में कार्य संचालन के लिए केवल हिंदी या अंग्रेजी ही भाषाएँ हो सकती हैं।
- पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.32) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य

संविधान ने राज्य की आधिकारिक भाषा को या हिंदी या अंग्रेजी को घोषित किया है, जिस भाषा में राज्य की विधायिका में कार्य संचालन हो सके।

पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

Q.33) जब कोई विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया जाता है तथा विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, तो उत्तराद्ध के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है?

1. यह विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयक को पारित कर सकता है
2. यह इसे विधानसभा में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है
3. यह विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकता है
4. यह कोई कार्रवाई नहीं करता है तथा इस प्रकार, विधेयक को लंबित रख सकता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1,2 और 4
- b) 1,3 और 4
- c) 1 और 2
- d) उपरोक्त सभी

Q.33) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य
जब कोई विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया जाता है तथा उसे विधान परिषद में प्रेषित किया जाता है, तो उत्तराद्ध के पास चार विकल्प होते हैं:			
1. यह विधानसभा द्वारा भेजे गए बिल को पारित कर सकता है (यानी, संशोधनों के बिना);			
2. यह संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर सकता है तथा इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस कर सकता है;			
3. यह बिल को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है; तथा			
4. यह कोई कार्रवाई नहीं करता है तथा इस प्रकार बिल को लंबित रख सकता है।			

Q.34) संविधान के तहत कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं प्रदान की गई हैं। ऐसे राज्यों में दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में

- a) राज्यपाल द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है तथा बहुमत से लिया गया निर्णय, अंतिम निर्णय के रूप में लिया जाता है
- b) विधेयक समाप्त हो जाता है, हालांकि समान विषय पर एक नया विधेयक, संशोधन के साथ फिर से प्रवर्तित किया जा सकता है।
- c) निर्दिष्ट अवधि के अंतराल के बाद, विधान सभा की राय को अंतिम रूप दिया जाता है
- d) मामला राष्ट्रपति के समक्ष निर्णय के लिए भेजा जाता है

Q.34) Solution (c)

कथन a	कथन b	कथन c	कथन d
असत्य	असत्य	सत्य	असत्य
साधारण विधेयक पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा में निहित होती है। सबसे अधिक, परिषद चार महीने की			

अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या देरी कर सकती है - पहली बार में तीन महीने और दूसरे चरण में एक महीने के लिए।

Q.35) विधान परिषद की शक्तियों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. परिषद न तो बजट पर चर्चा कर सकती है और न ही, अनुदानों की मांगों पर मतदान कर सकती है।
2. परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रियों की परिषद को हटा नहीं सकती है।
3. संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन में परिषद की कोई प्रभावी स्थिति नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.35) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
परिषद केवल बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान की मांगों (जो कि विधानसभा का विशिष्ट विशेषाधिकार है) पर मतदान नहीं कर सकती है।	परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रियों की परिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन, परिषद सरकार की नीतियों और गतिविधियों पर बहस और आलोचना कर सकती है।	संवैधानिक संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन में परिषद की कोई प्रभावी स्थिति नहीं है। इस संबंध में भी, विधानसभा की इच्छा परिषद से सर्वोच्च होती है

Q.36) केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक का पद राज्य के राज्यपाल के समान होता है।
2. संसद किसी राज्य के राज्यपाल को आसन्न संघ क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 36) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है	राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को आसन्न केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। उस क्षमता में, राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप

तथा राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है।

से कार्य करना होता है।

Q.37) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
2. संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए संवैधानिक प्रावधान अधिग्रहित प्रदेशों पर भी लागू होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.37) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूचियों (राज्य सूची सहित) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद की यह शक्ति जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली तक विस्तृत है, जिनकी अपनी स्थानीय विधायिकाएं हैं।	संविधान में अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। लेकिन, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए संवैधानिक प्रावधान अधिग्रहीत प्रदेशों पर भी लागू होते हैं।

Q.38) पुडुचेरी के मामले में, भारत के राष्ट्रपति केवल नियम बनाकर कानून बना सकते हैं

- a) जब संसद इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है
- b) जब विधानसभा उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है
- c) जब विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है
- d) जब उपराज्यपाल उसे करने का अनुरोध करते हैं

Q.38) Solution (c)

राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। पुडुचेरी के मामले में भी, राष्ट्रपति नियम बनाकर कानून बना सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब विधानसभा निलंबित या भंग कर दी गयी हो।

Q.39) विधान परिषदों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. विधान परिषदों के निर्माण के लिए, संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
2. संसद द्वारा विधान परिषदों का निर्माण, संविधान के अनुच्छेद 368 के संशोधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.39) Solution (b)

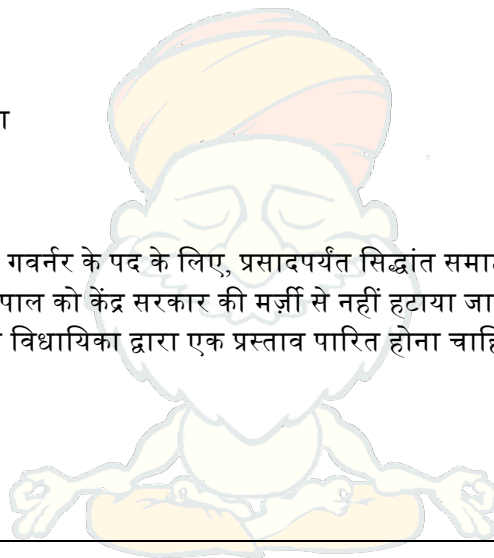
कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
संसद एक विधान परिषद (जहां यह पहले से मौजूद है) को समाप्त कर सकती है या इसे सृजित कर सकती है (जहां इसका अस्तित्व नहीं है), यदि संबंधित राज्य का विधान सभा उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है। इस तरह के एक विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात् विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत तथा विधानसभा के वर्तमान उपस्थित और मतदान करने वाले न्यूनतम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत। संसद के इस अधिनियम को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान के संशोधन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए तथा इसे विधान के एक साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है (अर्थात्, साधारण बहुमत द्वारा)।	

Q.40) निम्नलिखित में से किस आयोग ने सुझाव दिया था कि "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त के दौरान" वाक्यांश को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए?

- सरकारिया आयोग
- पूँछी आयोग
- वेंकटचलिया आयोग
- प्रशासनिक सुधार आयोग

Q.40) Solution (b)

पूँछी आयोग ने सिफारिश की कि- गवर्नर के पद के लिए, प्रसादपर्यन्त सिद्धांत समाप्त होना चाहिए तथा इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। राज्यपाल को केंद्र सरकार की मर्जी से नहीं हटाया जाना चाहिए। इसके बजाय, राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य विधायिका द्वारा एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए।



Copyright © by IASbaba

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.